

इंदिरा आवास के साथ शौचालय बनाने की जिम्मेवारी बीडीओ को

10 लाख शौचालय चार माह में बनाना चुनौती

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

एक सर्वे के अनुसार, खुले में शौच करने वाले लोगों में 60 फीसदी भारतीय हैं। राज्य में शौचालय से ज्यादा मोबाइल के कनेक्शन हैं। बिहार में खुले में शौच एक बड़ी समस्या है। पक्का घर बनाने के बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो शौचालय नहीं बनाते। खुले में शौच महिलाओं के लिए यातना जैसी है। इस स्थिति को बदलने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने अभियान चलाकर इस विनोद वर्ष यानी बचे हुए करीब चार महीने में 10 लाख शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा है। पीएचईडी ने भी पांच लाख शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा है।

लक्ष्य पाने को विभाग की पहल

पारिवारिक सर्वेक्षण की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में दो करोड़ 19 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें 17.2 फीसदी के पास ही शौचालय हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में शौचालय बनवाने के लिए केंवर जैस

तैयारी

- लाभुकों को ही इसे बनाने के लिए दिए जा रहे रुपये
- सर्वे के मुताबिक खुले में शौच करने वाले लोगों में 60 फीसदी भारतीय

(अभिप्रेरण) के तहत काम करने की योजना बनाई है। इसमें निर्मल भारत अभियान के तहत मनरेगा से भी शौचालय निर्माण कराए जा सकते हैं। एपीएल और बीपीएल दोनों वर्ग के लोगों को शौचालय निर्माण के लिए अब 4600 रुपये निर्मल भारत अभियान, मनरेगा से 4500 रुपये मिलेंगे। लाभुकों को 900 रुपये का योगदान करना होगा।

इंदिरा आवास पाने वाले लाभुकों को दूसरी किस्त तभी मिलेगी, जब वह शौचालय का निर्माण करा लेंगे। इसके लिए इन्हें 10 हजार रुपये अलग से दिए जाएंगे। इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण कराने की जिम्मेवारी बीडीओ पर होगी। इस वर्ष अब तक करीब छह लाख

लोगों को आवास दिए गए हैं। इस तरह छह लाख शौचालय का निर्माण पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत को भी शौचालय बनाने का भी लक्ष्य दिया गया है। इंदिरा आवास के लाभुकों को छोड़कर शौचालय निर्माण के लिए लोग पीओ या पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों का वरीयता क्रम के अनुसार शौचालय बनवाया जाएगा। इसमें एससी-एसटी, बीपीएल समेत अन्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

विभागीय सचिव अमृत लाल मीणा भी इतनी बड़ी संख्या में शौचालय निर्माण को चुनौती मानते हैं। हालांकि वह कहते हैं कि इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाएगा। अभियान चलाने के लिए बीडीओ, डीडीसी समेत तमाम पदाधिकारियों को खासतौर से निर्देश दिए गए हैं। किसी तरह की कोताही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक क्वालिटी की बात है, तो लोगों को इसका निर्माण खुद करना है, तो इसकी क्वालिटी खराब होने की आशंका कम है।